भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 758

04 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमृत 2.0 के अंतर्गत राजस्थान को आवंटित निधि

758. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत राजस्थान को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है और उसमें से जारी निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत लक्ष्यों के अनुरूप नागौर और डीडवाना-कुचामन सहित नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के जिलों और उक्त राज्य के अन्य जिलों में की गई वास्तविक प्रगति का जिला-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत , राजस्थान राज्य में केंद्रीय हिस्से के रूप में परियोजना कार्यान्वयन के लिए 3,552 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब तक, अमृत 2.0 परियोजनाओं के लिए राज्य को 745.45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी/स्वीकृत की जा चुकी है। अमृत 2.0 के तहत, परियोजना के लिए केन्द्रीय निधि ज़िले-वार नहीं बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को जारी की जाती है।

(ख): नागौर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, अमृत 2.0 के अंतर्गत आने वाले 13 कस्बों में 211.82 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। 64.26 करोड़ रुपए की 5

परियोजनाओं में कार्य सौंपा जा चुका है और 34.91 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य भौतिक रूप से पूरा हो चुका है। राज्य द्वारा अमृत 2.0 पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, कार्य सौंपे जाने वाली परियोजनाओं की ज़िले-वार भौतिक प्रगति अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) और (घ): अमृत दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशानिर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत 2.0 के तहत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए, स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। साथ ही, परियोजना के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/वर्कशॉप/साइट-विज़िट आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी और निगरानी के लिए एक विशिष्ट अमृत ऑनलाइन पोर्टल है।

*****

“अमृत 2.0 के अंतर्गत राजस्थान को आवंटित धनराशि” के संबंध में दिनांक 04/12/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 758 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक :

राजस्थान राज्य में उन परियोजनाओं का ज़िले-वार विवरण जिनमें ठेके दे दिए गए हैं

सम्पूर्ण राशि करोड़ रुपए में

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत की गई कुल परियोजनाएँ		परियोजनाओं के ठेके दिए गए		भौतिक प्रगति %
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	
2	अजमेर	15	705.22	4	346	71%
3	अलवर	13	630.95	7	354	15%
4	बांसवाड़ा	4	18.05	4	16	60%
5	बारां	9	145.56	2	59	55%
6	बाड़मेर	3	65.67	3	59	6%
7	भरतपुर	31	408.23	11	143	44%
8	भीलवाड़ा	10	413.95	3	212	67%
9	बीकानेर	2	293.48	2	269	53%
10	बूंदी	9	96.42	3	55	46%
11	चितौड़गढ़	11	181.23	9	154	14%
12	चुरू	16	341.62	13	259	60%
13	दौसा	7	33.40	-	-	-
14	धौलपुर	16	221.37	10	99	64%
15	गंगानगर	12	199.39	12	265	9%
16	हनुमानगढ़	13	177.85	9	153	34%
17	जयपुर	16	2,689.34	6	997	59%
18	जैसलमेर	4	33.15	3	29	8%
19	जालोर	6	75.08	5	59	6%
20	झालावाड़	6	126.92	4	110	32%
21	झुंझुनूं	10	196.85	7	139	27%
22	जोधपुर	15	1,329.85	8	443	57%
23	करौली	10	154.29	9	171	25%
24	कोटा	9	737.23	6	325	53%
25	नागौर	18	215.59	5	64	54%
26	पाली	18	253.94	15	197	22%
27	प्रतापगढ़	6	37.80	1	9	6%
28	राजसमंद	4	43.42	4	44	32%
29	सवाई माधोपुर	11	251.30	7	188	25%
30	सीकर	17	485.52	17	437	50%
31	सिरोही	9	92.20	4	9	4%
32	टोंक	15	157.50	9	107	60%
33	उदयपुर	7	454.93	6	207	65%

नागौर जिले में नागौर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 13 यूएलबी और राजसमंद संसदीय क्षेत्र का एक यूएलबी (डेगाना) शामिल हैं।

*****